



प्रेस विज्ञप्ति
21.11.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम क्षेत्रीय कार्यालय ने आईबीसी प्रक्रिया के दुरुपयोग के माध्यम से भूमि की कम कीमत पर बिक्री के संबंध में 20.11.2025 को दिल्ली और गुरुग्राम में छह स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी में बिचौलिए शामिल थे जो दिवाला प्रक्रिया का हिस्सा नहीं थे, समाधान पेशेवर, एनसीएलटी अधिवक्ता और संपत्ति के खरीदार मेसर्स आरडीबी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर लिमिटेड, जिसे विनोद दुग्गर द्वारा प्रचारित किया गया था।

ईडी ने मेसर्स यूनिवर्सल बिल्ड वेल प्राइवेट लिमिटेड और उसके प्रमोटरों के खिलाफ रियल एस्टेट परियोजनाओं को पूरा नहीं करने और घर खरीदारों और निवेशकों को धोखा देने के लिए दिल्ली एनसीआर में आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज 30 से अधिक एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

कंपनी ने बाद में सीआईआरपी की प्रक्रिया पूरी की, जिसके परिणामस्वरूप घर खरीदारों और अन्य वित्तीय लेनदारों से जुड़ी एक समाधान योजना को मंजूरी मिली, जिसमें एनसीएलटी ने कुछ संपत्तियों को घर खरीदारों को सौंपने का निर्देश दिया, जबकि शेष संपत्तियों को समाधान योजना के अनुसार बेचा जाना था।

जांच के दौरान, यह पाया गया कि जमीन को बहुत कम कीमत पर बेचा गया था। प्रस्तावित बिक्री के समय, सरकारी दरों पर भी संपत्ति का बाजार मूल्य प्रस्तावित बिक्री मूल्य से काफी अधिक था, जो प्रक्रिया से मुनाफा कमाने के प्रयास का संकेत देता है।

तदनुसार, पीएमएलए, 2002 की धारा 17 के तहत तलाशी कार्रवाई की गई, जिसके परिणामस्वरूप दो मध्यस्थों से लगभग 50 लाख रुपये की अस्पष्टीकृत नकदी जब्त की गई, जिसमें माननीय एनसीएलटी के समक्ष अभ्यास करने वाले एक अधिवक्ता भी शामिल थे, जो कम मूल्य के लेनदेन को सुविधाजनक बनाने में शामिल थे।

उनके मोबाइल फोन से बरामद डिजिटल डेटा में प्रस्तावित अवैध और बेहिसाब प्रतिफल को दर्शाने वाले ड्राफ्ट चालान थे, जो आईबीसी/एनसीएलटी ढांचे के बाहर और लेनदारों या एसआरए की ऐसी अनुमोदन प्रक्रिया के बिना अवैध लाभ के लिए व्यवस्थाओं को दर्शाते हैं।

तलाशी के दौरान एकत्र किए गए सबूतों से पता चला कि बोली प्रक्रिया में हेरफेर किया गया था, जिसमें पूर्व निर्धारित और कृत्रिम रूप से दबाई गई बोलियां शामिल थीं, जिसमें बिचौलिया वकील द्वारा खुद जमा की गई एक बोली भी शामिल थी, जो स्पष्ट मिलीभगत और बोली में हेराफेरी का संकेत देती है।

ईडी द्वारा बरामद सोशल मीडिया संचार से मध्यस्थों और एक निजी बैंक के एक अधिकारी के बीच संबंध भी स्थापित हुआ, जो एक सुरक्षित ऋणदाता था, जिसने बिक्री प्रक्रिया की देखरेख करते हुए अवमूल्यन योजना को सुविधाजनक बनाया था। निजी बैंक ने संपत्ति के मूल्य में महत्वपूर्ण वृद्धि के बावजूद कटौती की थी।

ई.डी. की जांच से यह भी पता चला कि संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करने में प्रत्यक्ष हिस्सेदारी रखने वाले घर खरीदारों (एस.आर.ए.) को जानबूझकर अनजान रखा गया था और जब्त की गई सामग्री समाधान पेशेवर की ओर से लापरवाही की ओर इशारा करती है।

आगे की जांच जारी है।